(b) and (c) There has been persistent demand from the State Govt. of Gujarat for shifting the office of Salt Commissioner from Jaipur to Gujarat. Keeping in view the administrative considerations, this proposal has not been agreed to.

New Research Centres in the country

*353. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV
SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the new Research Centres for Science, Technology, Food Research and Agriculture proposed to be set up during Eighth Five Year Plan in different parts of the country; and

(b) the number of such centres likely to be set up in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) There are a number of research centres already existing in the country covering fields of Science, Technology, Food Research and Agriculture in both the State and Central Sectors. No new research centres have so far been cleared for being set up in the country during the Eighth Five Year Plan.

(b) Does not arise.

Pipe water supply schemes in Maharashtra

*354. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to the Starred Question 338 given in the Rajya Sabha on 30th July, 1992 and State:

(a) whether the technical scrutiny of the 12 schemes proposed by the Government of Maharashtra under the Rajiv Gandhi Technology Mission has been completed;

(b) if so, what is the decision of Government thereon; and

(c) if not, what are the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Of the 12 schemes, the State Government was requested in August, 1992 to send details of project design for 11 schemes. The scheme for Gagangad water supply was not approved as at present, schemes for religious centres are not taken up.

(c) Does not arise.

श्रमिकों के पुनर्वास के लिए त्रिपक्षीय दल का विदेशों का दौरा

@ *355. **श्री वीरेन जे॰ शाह:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अतिरिक्त श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए त्रिपक्षीय (तीन दल) दल ने हाल में इंग्लैंड और हंगरी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल में कौन-कौन से राजनीतिक दल सम्मिलित थे और प्रत्येक राजनीतिक दल से कितने-कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे;

(ग) उक्त दल ने उपर्युक्त दो देशों के अतिरिक्त कौन-कौन से अन्य देशों का दौरा किया था और सरकार

@ पूर्वतः तारांकित प्रश्न 297, 14 दिसम्बर, 1992 से स्थानान्तरित।

को उक्त दल के दौरे के फलस्वरूप कितना व्यय वहन करना पड़ा;

(घ) क्या उक्त दल ने कोई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर "ना" में है तो ऐसा प्रतिवेदन कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और उसमें विलम्ब के क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) एक त्रिपक्षीय शिष्ट मंडल ने औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड और हंगरी का दौरा किया था।

(ख) शिष्ट मंडल में केवल केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

(ग) इंग्लैण्ड और हंगरी के अलावा किसी अन्य देश का दौरा नहीं किया था। दौरे पर हुआ पूर्ण व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) ने वहन किया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) दल ने सिफारिश की है कि भारत में औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इंग्लैण्ड और हंगरी के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Agreement for taking back spent fuel from the Tarapur Plant

*356. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in accordance with an agreement both USA and France are required to take back the spent fuel from the Tarapur Plant;

(b) whether it is also a fact that both USA and France have not adhered to the agreement so far; and

(c) if so, what are the reasons for their reluctance to take back the spent fuel in accordance with the agreement and what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) As per the agreements in respect of the Tarapur Atomic Power Station (TAPS), the fuel supplied both by USA and by France is the property of Government of India.

(b) and (c) Do not arise.

आई०आर०एच०पी०ए० के अधीन प्रदान की गई स्वीकृति

*357. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में "पावस" नामक परियोजना प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ आई०आर० एच०पी०ए० के अधीन 1988 में पांच वर्ष के लिए 90 लाख रूपये की राशि मंजूर की थी;

(ख) मंजूर की गई कुल राशि में से 30 जून, 1992 तक जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना की उपलब्धि लक्ष्य के अनुरूप रही है;

(घ) क्या उक्त विश्वविद्यालय ने इस परियोजना के संचालन में सहायता देने के लिए किसी विशेषज्ञ की मांग की थी; और

(ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किन-किन विश्वविद्यालयों में, विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत करके, अपने विशेषज्ञ भेजे थे और इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) से (घ) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के तीव्रीकरण के अधीन फंक्शनल पालिमर का प्रयोग करके फोटो